

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०/91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

# उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

#### विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 9 जून, 2022 ज्येष्ठ 19, 1944 शक सम्वत्

### उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या ४२४ / ग्यारह-2—22-9(47)—17-टी०सी०-183-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश (236)-2022 लखनऊ, ९ जून, 2022

#### अधिसूचना

#### प0आ0-125

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या क0नि0-2-136 / ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश—(99)-2018, दिनांक 30 जनवरी, 2018 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, चौथे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए प्ररूप जीएसटीआर—4 प्रस्तुत करने में विलंब के लिए संदेय विलंब फीस, दिनांक 1 मई, 2022 से 30 जून, 2022 तक की अवधि के लिए अधित्यजित रहेगी।"

2-यह अधिसूचना तारीख 26 मई, 2022 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से, नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव। IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government Notification no. 424 / XI-2-22-9(47)-17-T.C.183-U.P.Act-1-2017-Order-(236)-2022, dated June 9, 2022 :

No. 424 / XI-2-22-9(47)-17-T.C.183-U.P.Act-1-2017-Order-(236)-2022 Dated Lucknow, June 9, 2022

In exercise of the powers conferred by section 128 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification no. KA.NI.-2-136/XI-9(42)-17-U.P.Act-1-2017-Order-(99)-2018, dated Junaruy 30, 2018 namely:—

In the said notification, after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that the late fee payable for delay in furnishing of **FORM GSTR-4** for the Financial Year 2021-22 under section 47 of the said Act shall stand waived for the period from the 1<sup>st</sup> day of May, 2022 till the 30<sup>th</sup> day of June, 2022."

2. This notification shall be deemed to have come into force on the 26<sup>th</sup> May, 2022.

By order,
NITIN RAMESH GOKARN,
Pramukh Sachiv.